भारतीय वैश्विक
परिषद

पूर्वोत्तर एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों को समझना

क्षेत्रीय स्थिरता की खोज

आईसीडब्ल्यूए संवाद

भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली 2024

भारतीय वैश्विक
परिषद

पूर्वोत्तर एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों को समझना

क्षेत्रीय स्थिरता की खोज

आईसीडब्ल्यूए संवाद

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

2024

© आईसीडब्ल्यूए 2024

अस्वीकरण: इस लेख में प्रकाशित विचार, विश्लेषण और अनुशंसाएं वक्ताओं के निजी है।

विषयवस्तु

अवधारणा नोट 5

पूर्वोत्तर एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों को समझना
क्षेत्रीय स्थिरता की खोजः आईसीडब्ल्यूए संवाद 7

कार्यक्रम 41

बायो- प्रोफाइल 43

अवधारणा नोट

पूर्वोत्तर एशिया क्षेत्र जिसमें चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मंगोलिया और ताइवान शामिल हैं, एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र है जो ऐतिहासिक तनाव, आर्थिक परस्पर निर्भरता, क्षेत्रीय विवादों और बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए जाना जाता है। इस पैनल चर्चा का उद्देश्य क्षेत्र को आकार देने वाले प्रमुख विकासों, नई साझेदारियों और प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ इन रणनीतिक बदलावों का कारण बने अंतर्निहित हितों पर रौशनी डालना है।

मुख्य फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच विकसित हो रहे त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर होगा, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके विपरीत, पैनल एक समकक्ष तंत्र के रूप में रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते रणनीतिक और सामरिक सहयोग का भी पता लगाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना पर इसके संभावित प्रभावों की जांच भी करेगा। इसके अलावा, चर्चा में चीन- जापान- दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय वार्ता को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का विश्लेषण किया जाएगा और क्षेत्रीय गतिशीलता में परिवर्तन को देखते हुए इसके भावी प्रक्षेप पथ का आकलन किया जाएगा।

उत्तर कोरिया में जारी बैलिस्टिक मिसाइल उकसावे, परमाणु प्रसार गतिविधियाँ और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है एवं कोरियाई प्रायद्वीप पर परमाणु निरस्त्रीकरण की संभावनाओं को जटिल बनाती है। पैनल इन क्षेत्रों में हुए विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर उनके प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा, दो प्रमुख राष्ट्रों के बीच बसे, चारों तरफ से भूमि से घिरे देश- मंगोलिया की अद्वितीय स्थिति को इसके रणनीतिक संतुलन अधिनियम और क्षेत्रीय स्थिरता पहल में संभावित भूमिका को समझने हेतु विस्तार से पड़ताल करने की आवश्यकता है।

जनवरी 2024 में ताइवान के आम चुनावों के नतीजों के आधार पर, पैनल व्यापक क्षेत्रीय गतिशीलता के निहितार्थों की जांच करेगा। इस पैनल का उद्देश्य सभी हितधारकों के विविध दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए पूर्वोत्तर एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों की व्यापक समझ प्रदान करना और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने संबंधी चुनौतियों एवं अवसरों पर प्रकाश डालना है।

सप्रू हाउस

भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली

फरवरी 2024

पूर्वोत्तर एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों को समझना

क्षेत्रीय स्थिरता की खोज

आईसीडब्ल्यूए संवाद

सुश्री नूतन कपूर महावार

आईसीडब्ल्यूए में आपका स्वागत है! आईसीडब्ल्यूए ने कुछ समय से उत्तर- पूर्व एशिया पर चर्चा नहीं की है, हालांकि हमारे पास हमेशा एक या दो अध्येता होते हैं जो इस क्षेत्र पर ध्यान दे रहे होते हैं, अपनी नज़र रखते हैं और इसके बारे में लिखते रहते हैं। हालांकि, हमने दो कारणों से उत्तर- पूर्व एशिया पर अभी संवाद करने का निर्णय लिया है। पहला, इस क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और तनाव भी बढ़ रहा है। डीपीआरके के उत्तेजक एवं अप्रत्याशित व्यवहार और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह सच है कि चीन के आक्रामक व्यावहार एवं रवैये के कारण भी तनाव बढ़ रहा है। और इस संवाद को करने का दूसरा कारण है भारत का हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण जिसने इस क्षेत्र को हमारे करीब ला दिया है। इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा में हमारे गहरे हित हैं। क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं और क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव या शत्रुता का भारत समेत पूरे हिंद- प्रशांत क्षेत्र एवं नेविगेशन की स्वतंत्रता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा एवं व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, हमने परिस्थिति का आकलन करने, इस क्षेत्र में गठबंधन एवं काउंटर-गठबंधन की स्थिति क्या है, का आकलन करने एवं बातचीत और कूटनीति के आधार पर शांति एवं सुरक्षा के मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही इस संवाद का निर्णय लिया था। इससे पहले कि मैं राजदूत तयाल को संवाद की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करूँ, मैं आईसीडब्ल्यूए की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह की ओर से यहां उपस्थित न हो पाने पर खेद व्यक्त करना चाहूँगी। वो इस संवाद का हिस्सा बनने को उत्सुक थीं। लेकिन उन्हें किसी और बैठक में शामिल होने के लिए बुला लिया गया था; जिसके बारे में उन्हें कल ही पता चला।

इसके साथ ही, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। राजदूत तयाल।

राजदूत स्कंद तयाल

बहुत- बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आईसीडब्ल्यूए की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे समय में इस संवाद का आयोजन किया है जहां सबकुछ बदलता हुआ दिख रहा है। सभी पुरानी निश्चितताएं अनिश्चितता के क्षेत्र में जा चुकी हैं। और पिछले दो, तीन दशकों से, एक निश्चित संतुलन बना हुआ था।

एक निश्चित यथास्थिति बनी हुई थी लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ दिख रहा है। और यह बिल्कुल सही समय है कि हम सामूहिक रूप से इस बात पर चर्चा करें कि क्या होने की संभावना है। और मुझे इस बेहद सारगर्भित अवधारणा नोट की भी सराहना करनी चाहिए। यह एक बड़ी पहेली है लेकिन आपने पहेली में उन प्रमुख रिक्त स्थानों की पहचान कर ली है जिन्हें भरा जाना है। इसलिए, मैं अपने अध्यक्ष की टिप्पणियों को अपनी टिप्पणियों के साथ मिलाउंगा और कुछ ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करूंगा जिन्हें यह बेहद ही सम्मानित पैनल संबोधित करना चाहेगा।

अब, अवधारणा नोट में, तीन या चार अलग- अलग क्षेत्रों की पहचान की गई है। मैं एक-एक कर सब पर बात करूँगा। पहला- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका- जापान- दक्षिण कोरिया। अब, हम सब कैंप डेविड समझौते के तहत 18 अगस्त 2023 को की गई घोषणा के बारे में जानते हैं, जो कई मायनों में परिस्थितियों को बदलने वाला था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अपने दो रक्षा सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाने के लिए कई दशकों, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के समय से ही प्रयास कर रहा था, और ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस स्तर तक आना राष्ट्रपति यून और प्रधानमंत्री किशिदा, दोनों ही के लिए बहुत साहसिक रहा है। और उत्तर पूर्व एशिया में दिलचस्पी रखने वाले हम सभी लोगों के लिए उस दस्तावेज को विस्तार से पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि इसमें चीन के "खतरनाक और आक्रामक व्यवहार" पर चिंता व्यक्त की गई है। दक्षिण चीन सागर में, इसमें ताइवान का उल्लेख है, ताइवान जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया है। इसलिए, कई मायनों में यह त्रिपक्षीय सहयोग या उभरते त्रिपक्षीय सहयोग के क्षेत्र को कोरियाई प्रायद्वीप और उत्तर पूर्व एशिया से परे ताइवान जलडमरूमध्य और हिंद- प्रशांत, पूरे हिंद- प्रशांत और उससे आगे तक विस्तारित करता है। एक बिंदु पर वे हिंद- प्रशांत और उससे परे की बात करते हैं।

इसलिए, यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाना चाहेगा। वे कितने दबाव में आएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चीन और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन और जापान के बीच भी संबंध अच्छे नहीं हैं। मई 2023 में एक रेडियो कार्यक्रम में, दक्षिण कोरिया में चीन के राजदूत ने कहा था "सच कहूँ तो चीन और दक्षिण कोरिया के बीच वर्तमान संबंध अच्छे नहीं हैं और इनके और खराब होने का खतरा है।"

लेकिन कुछ मुद्दे हैं। क्या कोरिया- जापान संबंधों में यह बदलाव लंबे समय तक चल सकेंगे? राष्ट्रपति यून एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नियमित अंतराल पर राष्ट्रपति बदल जाते हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल पांच वर्षों का होता है। राष्ट्रपति यून की अनुमोदन रेटिंग 34% है। अस्वीकृति रेटिंग 59% है, 59% अस्वीकृति - तटस्थ भी नहीं है। 10 अप्रैल 2024 को नेशनल असेम्ब्ली के चुनाव होने हैं। तो क्या जापान और कोरिया की यह नज़दीकी, जो वास्तव में थोपी गई है, लंबे समय तक नहीं चल सकेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

फिर यदि राष्ट्रपति ट्रम्प फिर से सत्ता में आते हैं, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। वे लेन- देन वाले संबंधों में अधिक विश्वास रखते हैं और हमें याद है कि अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति ट्रम्प दक्षिण कोरिया में तैनात 28,000 अमेरिकी सैनिकों के लिए 5 अरब डॉलर का भुगतान करने का दबाव बना रहे थे, और बहुत बातचीत के बाद, मुझे लगता है कि 1 अरब डॉलर देने पर सहमति बन सकी थी लेकिन वे सभी मुद्दे फिर से सिर उठाएंगे। इसलिए, उस समय दक्षिण कोरिया और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच बहुत मित्रवत संबंध नहीं थे। इसलिए, क्या संबंधों की शुरूआत वहीं से होगी, यह देखने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा।

फिर पहेली का दूसरा रिक्त स्थान या हिस्सा, रूस- चीन- उत्तर कोरिया। मुझे लगता है कि पिछले शायद दो वर्षों में खासकर यूक्रेन- रूस युद्ध के बाद से, एक बड़ा बदलाव आया है। सितंबर 2023 में, अध्यक्ष किम जोंग-उन की रूस यात्रा के दौरान, उन्होंने कुछ कॉस्मोड्रोम का भी दौरा किया था और उसके बाद ही उत्तर कोरिया ने जासूसी कर सकने वाले उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। उत्तर कोरिया के मुखिया ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, उनके उप रक्षा मंत्री हाल ही में रूस में थे और राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया के दौरे की बात की जा रही है। दक्षिण कोरियाई खुफिया विभाग की ओर से बताया गया कि यूक्रेन में इस्तेमाल किए जाने के लिए उत्तर कोरिया ने रूस को 24.5 अरब डॉलर मूल्य के दस लाख गोले उपलब्ध कराने के अनुबंध पर सहमति जताई है।

अब एक बात तो तय है कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसे चीन का पूरा समर्थन है। उत्तर कोरिया जैसे देश के लिए, जो उसकी अर्थव्यवस्था का आकार है, विनिर्माण, इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री, मिश्रित सामग्री, यहां तक कि गोले बनाने के लिए बहुत सारी बैकअप तकनीक और आपूर्ति की आवश्यकता होगी, यह कहाँ से आ रही है? मुझे हमेशा से लगता है कि चीन किसी- न- किसी रूप में उसकी मदद कर रहा है। फिर राष्ट्रपति यून और प्रधानमंत्री किशिदा दोनों द्वारा ठोस रूस विरोधी रूख अपनाए जाने पर राष्ट्रपति पुतिन बहुत परेशान होंगे। यूक्रेन के लिए खुला समर्थन और नाटो

शिखर सम्मेलन, 2022 और 2023, मैड्रिड, विलनियस में, दोनों देशों ने हिस्सा लिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

इसलिए वर्तमान नेतृत्व में, जापान और दक्षिण कोरिया ने रूस और रूस के खिलाफ खुला विरोधी रूख अपनाया हुआ है और रूस इसे नहीं भूलेगा।

अब, तीसरा हिस्सा, चीन- जापान- दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय वार्ता, जो 2008 से कभी होती है और कभी नहीं, लेकिन ये पुरानी बात है, तब शी जिनपिंग नहीं थे। साल 2008 से शिखर सम्मेलन हुए लेकिन फिर कोविड आ गया और स्थितियां बदल गईं। मेरा अपना मानना है कि वर्तमान यून शासन बहुत हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्षधर है। इनके पूर्व विदेश मंत्री पार्क जिन, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था, जब मैं सियोल में राजदूत था, वे नेशनल असेम्ब्ली में सदस्य थे और दक्षिण कोरिया- यूएस फ्रेंडशिप सोसायटी के अध्यक्ष भी। राष्ट्रपति यून के सभी करीबी सलाहकार खुले तौर पर अमेरिका के पक्षधर हैं, इसलिए, मुझे इस शिखर सम्मेलनय से या राष्ट्रपति यून के कार्यकाल में शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने पर भी मुझे कुछ ठोस होने की उम्मीद नहीं है। यदि सच में कोई नतीजा निकलता है, भले ही वह त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हो, तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन ये जिन मुद्दों के बारे में बात की जा रही है, मुझे लगता है नेशल असेम्ब्ली के चुनाव के बाद, कुछ लोगों का कहना है कि चीन इन पर विचार कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा।

अब अवधारणा पत्र का चौथा भाग, नवंबर 2023 में उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल और मल्लीगयोंग- 1 जैसे जासूसी उपग्रहमों को लॉन्च किया और यह निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध नीति का उल्लंघन है, लेकिन इस संबंध में भी कोई देश कुछ नहीं कर सका। और हाल में कुछ रिपोर्ट आई थी, उत्तर कोरिया की एजेंसी ने कहा था कि इस उपग्रह ने ह्वाइट हाउस, पेंटागन और अमेरिकी विमान वाहक स्थलों की विस्तृत तस्वीरें खींची हैं।

इससे अमेरिकियों और दक्षिण कोरियाओं के बीच जापान के साथ कुछ और ख़ुफिया जानकारियों का आदान- प्रदान हुआ और इस बात पर भी सहमति बनी कि उनके पास उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, वे वास्तविक समय पर साझा किए जाएंगे। तो कैंप डेविड अनुबंध, इसका कुछ हिस्सा पहले से ही लागू किया जा रहा है।

अगर हम परिस्थितियों पर गौर कर भविष्यवाणी करना चाहें तो यह कहना उचित होगा कि उत्तर कोरिया का परमाणु निरस्त्रीकरण कल्पना भर है। अगर लोग समय काटना चाहें तो इस बारे में बात कर सकते हैं लेकिन अगर राष्ट्रपति ट्रम्प फिर से सत्ता में लौटते हैं तो नतीजा संयुक्त राष्ट्र द्वारा विस्तारित प्रतिरोध कैंप डेविड में उल्लिखित मजबूती जितना ही 'दृढ़' होगा। क्या सच में मजबूत होगा? और यह सवाल निश्चित रूप से कुछ लोग टोक्यो और सियोल दोनों में पूछ रहे होंगे और वे इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे, इस पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे। मुझे हमेशा लगता है कि अगर राष्ट्रपति ट्रम्प सत्ता में रहे तो वे जापान को परमाणु शक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं कोरिया के बारे में तो यकीन से नहीं कह सकता लेकिन जापान के बारे में कह सकता हूँ। कैंप डेविड समझौता यही कहता है कि वे बिना किसी पूर्व शर्तों के डीपीआरके के साथ संवाद स्थापित करने को प्रतिबद्ध हैं। इसलिए, यह अनिश्चितताओं का क्षेत्र है।

फिर ताइवान के चुनावों ने भी इस पूरे मामले में कुछ और अनिश्चितता ला दी है। कल दो चीनी मछुआरों की मौत हो गई थी। निश्चित रूप से, चीन के नाविक अलग- अलग देशों की जल सीमा में मछली पकड़ते हैं, चाहे वह जापान हो, कोरिया हो और या बेशक, दक्षिण चीन सागर हो, हर जगह। लेकिन चीन के दो मछुआरों की मौत ताइवान के तटरक्षक बल द्वारा पीछा किए जाने के दौरान हुई। राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान दिया था कि अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ताइवान पर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मेरी अपनी समझ कहती है कि ताइवान को स्थितियों को बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि वे धीरे- धीरे अधिक स्वाधीनता की ओर बढ़ते हैं तो चीन बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है और अमेरिका पहले से ही दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों- यूक्रेन और गाज़ा में उलझा हुआ है।

इसलिए ताइवान को चीन को नहीं भड़काना चाहिए। यह मेरी अपनी समझ है।

अब अगर हम इन सभी बड़ी पहेलियों को देखें तो वहां मौजूद अलग- अलग देशों के अनिश्चित क्षेत्र या अनिश्चित प्रक्षेप पथ क्या हैं? एक, मेरे विचार से, जापान-दक्षिण कोरिया संबंध, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, कि यह स्थायी है। यह कभी भी खराब हो सकता है। मुझे लगता है कि दक्षिण कोरियाई अदालत ने फिर से जापानी कंपनियों से कोरियाई बंधुआ मजदूरों के मुआवज़े की मांग की है- एक ऐसा मुद्दा जो विश्व युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच चला आ रहा है।

दूसरा, कोरिया गणराज्य और जापान में परमाणु ऊर्जा के लिए जनता का समर्थन कैसा होगा? सभी सार्वजनिक सर्वेक्षणों का यही कहना है कि 70%, 75% दक्षिण कोरियाई लोग चाहते हैं कि दक्षिण कोरिया परमाणु ऊर्जा संपन्न हो। निश्चित रूप से, जापान में स्थिति अलग है। लेकिन कब तक रहेगी? ताइवान ने चीन को चुनौती देने का संकल्प लिया है।
वे अमेरिकी कांग्रेसियों को ताइवान जाने के लिए प्रेरित करते हैं, बड़ी संख्या में कैबिनेट सदस्य ताइवान का दौरा कर रहे हैं। ताइवान धीरे- धीरे अपनी वास्तविक स्वतंत्रता पर ज़ोर दे रहा है।
लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक सीमा के बाद चीन जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है।

फिर, निश्चित रूप से एक और अनिश्चित प्रक्षेपवक्र है- अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति ट्रम्प बहुत अप्रत्याशित हैं, इसलिए वे कब, कहां, किस क्षेत्र या इलाके में क्या कर देंगे, किसी को नहीं पता होता। लेकिन उनकी सामान्य प्रवृत्ति राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में किए गए कार्यों को बदलना या पलटना होगा। यह हिंद- प्रशांत, इनके सहयोगियों पर कितना लागू होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया, सारे संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं, तो हिंद- प्रशांत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिकी सहयोगी क्या सोचेंगे? मेरा मानना है कि जापान हर संभव तरीके से स्वयं की आत्मरक्षा को मजबूत बनाएगा।

और फिर अधिक पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि उत्तर कोरिया के साथ रूस की रक्षा साझेदारी बढ़ जाए। इसमें उपग्रह प्रक्षेपण के लिए रूस जो भी सहायता कर सकता है करेगा और इसमें चीन भी पूरी तरह से मदद करेगा। इसलिए मेरे विचार से रूस और उत्तर कोरिया के रक्षा और आर्थिक संबंध के बहुआयामी स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है।

चीन के साथ रूस की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी अधिक अनुमानित है, केवल उसकी गति अनिश्चित है। उत्तर कोरिया अपनी क्षमताओं, मिसाइल निर्माण, मिसाइल प्रक्षेपण, पानी के नीचे, पनडुब्बी आधारित, सभी आयामों में विकास जारी रखेगा ताकि अमेरिका को इसकी वास्तविक क्षमताओं एवं समर्थतताओं से अनजान रखा जा सके। दक्षिण चीन सागर और सेनकाकू द्वीप समूह के आस-पास चीन की विस्तारवादी चालें जारी रहेंगी। और चीन अलग- अलग तरीकों, जैसे हवाई और नौसैनिक अभियानों आदि से ताइवान को डराना- धमकाना भी जारी रखेगा।

पूर्वोत्तर एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों को समझना: क्षेत्रीय स्थिरता की खोज: आईसीडब्ल्यूए संवाद 14

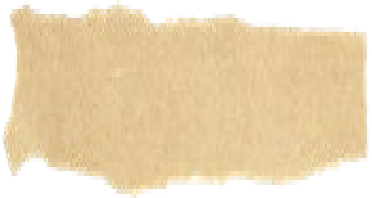

डॉ. संदीप मिश्रा

इन टिप्पणियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। हमारे पास विशेषज्ञों का बेहद प्रतिष्ठित पैनल है। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इस पर समय बर्बाद नहीं करूँगा। कार्यक्रम के अनुसार, सबसे पहले मैं सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर और दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे पूर्व सहयोगी डॉ. संदीप कुमार मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ। संदीप?

धन्यवाद महोदय। आईसीडब्ल्यूए द्वारा आमंत्रित किया जाना बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने इस गोलमेज़ सम्मेलन के विचार की संकल्पना की है, उन्होंने, बहुत, बहुत, आप कह सकते हैं कि, गहन विचार किया है। शीर्षक, अवधारणा पत्र त्रुटिहीन था इसलिए मैं सबसे पहले उसकी सराहना करना चाहता हूँ।

अब, उत्तर पूर्व एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने कोरिया के मामलों पर विशेषज्ञता अर्जित की है, इसलिए मैं कोरिया के बारे में बाद में बात करूँगा। पहले मैं इस पूर्व एशिया की समस्या में कोरिया की स्थिति बताने की कोशिश करूँगा।

अगर मैं उत्तर पूर्व एशिया पर गौर करूँ, तो ऐतिहासिक रूप से वहां वास्तव में, जैसा कि विक्टर चा नाम के विद्वान ने बताया है, दो आभासी- गठबंधन रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, चीन और रूस (पहले सोवियत

सं
घ
)
।
ये

दोनों ही गठबंधन शीत युद्ध के युग में एक-
दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और अब
वर्तमान स्थितियों, जब की अनिश्चितताएं
अधिक प्रमुख हो चुकी हैं, के विपरीत चीजें
बहुत निश्चित थीं।

शीत युद्ध के बाद की अवधि में, पुरानी निश्चितताएं समाप्त हो गई थीं और यह एक अच्छी बात लगी क्योंकि वास्तव में एक आभासी- गठबंधन के देशों ने दूसरे देशों से संपर्क करना आरंभ कर दिया जैसे कि दक्षिण कोरिया ने रूस और चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। यहां तक कि 1990 की दशक की शुरुआत में जापान ने भी उत्तर कोरिया के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया और संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई दौर की वार्ता हुई, हालांकि वार्ता असफल रही।

हालांकि, अगले चरण में, दो आभासी गठबंधनों के देशों के बीच पहुँच कम होती गई क्योंकि उत्तर कोरियाई परमाणु मुद्दा इस क्षेत्र में सबसे विवादास्पद मुद्दा बन गया। एक तरह से संरचनात्मक स्तर पर, दो आभासी- गठबंधन के अस्तित्व ने क्षेत्र में अधिक सूराखदार और कमज़ोर प्रतियोगिताओं का मार्ग प्रशस्त किया लेकिन उत्तर कोरियाई परमाणु मुद्दे के उभरने से समीकरणों का पुनर्गठन हुआ जिसमें पुराने आभासी- गठबंधन को फिर से प्रमुखता मिली।

अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और क्षेत्र की समकालीन वास्तविकता को देखें, तो मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर एशिया में दो महत्वपूर्ण रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक, मुखर चीन का उदय, आदान- प्रदान के सभी क्षेत्रों में चीन अपनी भूमिका पर ज़ोर देने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में चीन ने पहले से ही अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बना रखा है। यदि आप क्रय शक्ति समता को देखें तो चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 28 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। देखा जाए तो यह अंतर बहुत अधिक का नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार 27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है जबकि चीन की अर्थव्यवस्था का आकार 18 ट्रिलियन डॉलर का। चीन, संयुक्त राष्ट्र में शामिल विश्व के 193 देशों में से 120 देशों का पहले नंबर का व्यापारिक साझीदार है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में, चीन ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की शुरुआत की और हम जानते हैं कि वे कैसे इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी बन गए हैं।

सुरक्षा के क्षेत्र में भी चीन काफी मुखर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे वे दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और यहाँ तक कि हिंद महासागर में भी नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए, ये सभी चीजें पूर्वोतर एशिया में पहली बड़ी प्रवृत्ति का समर्थन कर रही हैं जो समकालीन काल में हो रही हैं। क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आक्रामक चीन के उदय से निपटने के लिए अमेरिकी प्रतिक्रिया है। अमेरिका चीन से मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, कम- से- कम ट्रम्प के कार्यकाल से, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ गया है।

दूसरा, अमेरिका इस क्षेत्र में जापान, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे कुछ अन्य देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। और क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से भी अमेरिका अपने सहयोगी देशों और मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर चीन से निपटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा तब और अधिक बढ़ गई जब 2022 में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया और जब फरवरी 2023 में अमेरिका ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में चीनी गुब्बारे मार गिए थे।

लेकिन अगर आप 2023 के उत्तरार्ध को देखें तो आप देख पाएंगे कि अमेरिका और तीन किस तरह से अपने मुकाबले को सीमित करने के लिए कोई- न- कोई तरीका ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी व्यापक प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में, वे किसी प्रकार की परिचालन स्थिरता चाहते हैं। इसलिए, 2023 के मध्य से, अमेरिका और चीन एक- दूसरे देशों में उच्चाधिकारियों की यात्राओं की संख्या बढ़ाने और विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। मई 2023 में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन के मौके पर एक बैठक की। अमेरिकी विदेश सचिव ब्लिंकन ने जून 2023 में चीन का दौरा किया, जुलाई 2023 में अमेरिका के राजकोष सचिव ने चीन का दौरा किया और अमेरिका एवं चीन के बीच उच्च- स्तर के कई अन्य बैठकें हुईं। और आखिरकार, नवंबर 2023 में, एपेक (APEC) की बैठक के दौरान शी जिनपिंग और बाइडेन ने, अलग से, चार घंटों की बैठक की। अभी हाल ही में, जनवरी 2024 में, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बैंकॉक में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी।

इसलिए, मुझे लगता है कि दोनों देश पिछले कुछ महीनों में संबंध बनाने के प्रयास कर रहे हैं। एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका प्रौद्योगिकी, उन्नत माइक्रोचिप्स और एआई तकनीक के क्षेत्र को छोड़कर चीन के साथ व्यापाक संबंध स्थापित करने को तैयार है।

पूर्वोत्तर एशिया में एक और महत्वपूर्ण विकास को त्रिपक्षीय रूपरेका में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के एक दूसरे के करीब आने के रूप में देखा जा सकता है। कैंप डेविड में तीनों देशों का त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ था और हाल के महीनों में उनकी नीतों के समन्वय हेतु कई कदम उठाए गए हैं। 15-17 जनवरी 2024 को, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने दक्षिण कोरिया के तट पर तीन दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया था जिसे अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास माना जा रहा है क्योंकि इसमें नौ से अधिक बड़े विध्वंसक पोतों ने हिस्सा लिया था। इसलिए, मुझे लगता है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को समन्वित एवं मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

अब मैं कोरियाई प्रायद्वीप पर हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बात करना चाहूँगा। वर्ष 2018 के बाद, एक सकारात्मक माहौल बना था क्योंकि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने, 2018 और 2019 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ तीन बैठकें की थीं। किम जोंग- उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई- इन के साथ भी चार बैठकें की थी। वर्ष 2018 में, दोनों कोरिया के बीच एक सैन्य समझौते के साथ पनमुनजोम घोषणा की गई थी जिसे एक प्रकार का सीबीएम कहा जा सकता है। एक समय अंतर- कोरिया संबंधों के लिहाज़ से यह एक अच्छा दौर था।

लेकिन 2020 के बाद से या यूँ कहें कि फरवरी 2019 में हनोई में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच हुई दूसरे शिखर सम्मेलन, जो असफल रहा, से, आप देख सकते हैं कि संबंध कमजोर हुए और उत्तर कोरिया उत्तरोत्तर आक्रामक होता जा रहा है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन इतना कहना पर्याप्त होगा कि 2022 में, उत्तर कोरिया ने 80 से अधिक मिसाइलों का परीक्षण किया और 2023 में इसने करीब 40 मिसाइलों का परीक्षण किया, इनमें ह्वासोंग-18 समेत पांच अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं।

इसलिए, मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया पिछले कुछ वर्षों में काफी आक्रामक रहा है। साल 2024 में भी, उत्तर कोरिया का आक्रामक रवैया जारी है और जनवरी 2024 में, उत्तर कोरिया ने उत्तरी सीमा रेखा (एनएलएल), जो मूल रूप से दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की सीमारेखा है, के पार कुछ गोले दागे। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर उसे उकसाया गया तो वो दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे।
हाल के महीनों में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की ओर के कई तीखे बयान आए हैं।

मैं कहूँगा कि, जब मैं उत्तर और दक्षिण कोरिया के संबंधों को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि दक्षिण कोरिया में वर्तमान प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब जाने की कोशिश की है और उन्हें मूल रूप से उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों की उपेक्षा की है। ऐसा लगता है कि अगर उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को छोड़ने से इनकार कर देता है तो उनके पास उत्तर कोरिया से निपटने की कोई दूसरी योजना नहीं है। अंतर-कोरिया संबंधों में वर्तमान गतिरोध तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के प्रति अपने पारस्परिक दृष्टिकोण से परे नहीं सोचता। वर्तमान दक्षिण कोरियाई सरकार का उत्तर कोरिया पर कड़ा रुख, जैसे- को- तैसा करने की नीति, नाटो शिखर सम्मेलन में जाना, अमेरिकी सामरिक परमाणु हथियारों को फिर से आमंत्रित करना, निकट भविष्य में अंतर-कोरिया संबंधों में कोई सुधार नहीं ला पाएगा।

एक अजीबोगरीब तरीके से, उत्तर कोरिया को पिछले कुछ महीनों में एक अवसर मिला है, विशेषरूप से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद। अब उत्तर कोरिया रूस के साथ मिल कर काम कर रहा है और जैसा कि राजदूत तयाल ने बताया, नवंबर 2023 में उसने अपना जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिया है। इसके बदले में उत्तर कोरिया यूक्रेन से युद्ध में रूस को मदद करने के लिए सैन्य उपकरण और गोला- बारुद उपलब्ध करा रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल के दिनों में चीन के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाया है।

इसलिए, अपनी प्रस्तुति के आखिर में अगर मुझे संक्षेप में कहना हो कि पूर्वोत्तर एशिया में क्या हो रहा है तो मैं कहूँगा कि बीते दो, तीन वर्षों में, निश्चित रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत हुआ है, हालांकि, जैसा कि राजदूत तयाल ने बताया, हमें यकीन नहीं है कि यह गठबंधन कितने समय तक चलेगा और इसे अमेरिका के लिए एक अच्छी बात के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

हालाँकि, साथ ही, हम यह भी देखते हैं कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया और यहाँ तक कि ईरान जैसे अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों का संबंध एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि उसके द्वारा उठाए गए कदमों से न केवल मित्र राष्ट्रों बल्कि प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र भी एकजुट हुए हैं।

आखिर में, मैं कहूँगा कि आने वाले महीनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और उन घटनाओं को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले, जैसा कि राजदूत तयाल ने बताया, अप्रैल 2024 में दक्षिण कोरिया के संसदीय चुनाव होने हैं।
दूसरा, नवंबर 2024 में, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। तीसरा, 2024 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन हो सकता है। नवंबर 2023 में, काफी समय के बाद दक्षिण कोरिया में, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक हुई थी और आशा है कि जल्द ही इन देशों के बीच शिखर सम्मेलन हो सकता है। मेरे विचार से, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं और ये पूर्वोत्तर एशियाई परिस्थितियों की भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं।

अपने व्याख्यान को समाप्त करने से पहले, मैं इस क्षेत्र में हुए एक और दिलचस्प विकास की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हाल ही में, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि वह उत्तर कोरिया के नेता के साथ शिखर सम्मेलन करना चाहेंगे और उत्तर कोरिया के नेता की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बहन किम यो-जोंग ने उत्तर में कहा कि उत्तर कोरिया जापान के साथ ऐसे किसी भी शिखर सम्मेलन को लेकर सकारात्मक रवैया रखता है। इन सभी घटनाक्रमों का क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं और इसकी परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ने वाला है और हमें उन पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

राजदूत स्कंद तयाल

धन्यवाद, डॉ. मिश्रा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा। क्या हम फिर से दो गुटों रूस- चीन- डीपीआरके और अमेरिका- जापान- आरओके के उदय के साक्षी बन रहे हैं? प्रोफेसर महापात्रा, अब आपकी बारी।

प्रो. चिंतामणि महापात्रा

अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं, उत्तर पूर्व एशिया में हो रहे बेहद खतरनाक घटनाक्रमों पर अपने कुछ विचार साझा करने के लिए मिले इस अवसर का आभारी हूँ। मैं मूल रूप से तीन विषयों पर बात करूंगा। अभी क्या हो रहा है? प्रमुख रुझान क्या हैं? भविष्य में क्या होने की संभावना है?–एक प्रकार की राजनीतिक ज्योतिषीय गणना। वर्तमान में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, उत्तर पूर्व एशिया में बहुत ही जटिल शीत युद्ध विकसित हो चुका है। और राजदूत महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नए प्रकार के समूह सामने आए हैं, विशेष रूप से रूस, चीन और उत्तर कोरिया और यूक्रेन युद्ध के बीच ये त्रिकोणीय संबंध गहरे भी होते जा रहे हैं। चीन, रूस और उत्तर कोरिया, ये तीन देश महसूस कर रहे हैं कि वे मुख्यधारा के अंतरराष्ट्रीय संबंधों से राजनीतिक रूप से अलग- थलग पड़ गए हैं। इन तीनों देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान ने भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं। और ये तीनों एक प्रकार से एक नई वैश्विक व्यवस्था चाहते हैं जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व न हो। जब अमेरिकी नियम- आधारित व्यवस्था के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में बनाई थी, और कहते हैं कि इस व्यवस्था में चुनौतियां हैं, तो ये तीनों देश कहते हैं कि, "किसके नियम"? ये नियम किसने बनाए? हम नए नियम क्यों नहीं बना सकते? दूसरी तरफ, अमेरिका- जापान- दक्षिण कोरिया ने कैंप डेविड समझौता नाम का अनुबंध कर रखा है जो इस दिशा में हुआ नया विकास है।

दशकों से, जापानी और दक्षिण कोरियाई एक- दूसरे से नफ़रत करते थे, ऐतिहासिक कारणों से एक- दूसरे को नापसंद करते थे और उनके बीच क्षेत्रीय विवाद भी थे। और अब, बहुत संघर्ष के बाद, अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं को एक साथ लाने में सफल हुआ है, उसने कैंप डेविड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए। यदि आप विवरण देखें तो यह बहुत स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर एशिया में दो नए और विरोधी रणनीतिक त्रिकोण आकार ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यह नया शीत युद्ध जो मैं देख रहा हूँ वह केवल गुट बनाने तक ही सीमित नहीं है।

यह अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है, अमेरिका और चीन के बीच एक प्रकार का सीमा- शुल्क विवाद अभी भी जारी है। चीन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया के व्यापारिक संबंधों में फिलहाल गिरावट देखी जा रही है। इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि चीन की अर्थव्यस्था में मंदी आ रही है। चीन के स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य 2021 की तुलना में 20% कम हो गया है। देश एक प्रकार की ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है और सार्वजनिक ऋण की राशि भी बहुत बड़ी है, खरबों डॉलर की। और ऋण- जीडीपी अनुपात के संदर्भ में, अब यह चीन के सकल घरेलू उत्पाद के 290% से अधिक है। जबकि विकसित देशों में ऋण- जीडीपी का अनुपात 250-260% का है।

हालाँकि अमेरिकी ह्वाइट हाउस का दावा है कि उसके पास इसके रोकथाम का कोई सिद्धांत नहीं है, कुछ अमेरिकी कार्रवाइयां अन्यथा संकेत दे रही हैं। अमेरिकी सरकार यह नहीं कहना चाहती कि उसकी नीति चीन को रोकने की है। लेकिन अमेरिका की कुछ प्रकार की रोकथाम नीति उन लोगों को समझ में आती है जो वहां के घटनाक्रम पर उत्सुकता के साथ नज़र रख रहे हैं। चीन को नियंत्रित करने की अमेरिकी प्रयास स्पष्ट रूप से तब परिलक्षित होते हैं जब अमेरिका अपने सहयोगियों को ऑफ- शोरिंग और फ्रेंड- शोरिंग या चीन को दरकिनार करते हुए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जी7 और अन्य मंचों के माध्यम से चीनी बीआरआई के लिए कुछ प्रकार की वैकल्पिक कनेक्टिविटी पहल हेतु कदम उठाए हैं। बीआरआई मूल रूप से एक हब और प्रमुख व्यावसारिक संरचना है। चीन इसे धन उपलब्ध कराता है, बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे लाइनों एवं एशिया और यूरोप के अलग- अलग परिवहन गलियारों में विभिन्न संरचनात्मक निर्माण हेतु इंजीनियरों, पूंजी, तकनीशियनों एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार, चीन केंद्र है और चीन से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य देश प्रवक्ता। जबकि अमेरिकी अधिक पारदर्शी और ऋण-संवहनीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन कर रहे हैं, चीन का बीआरआई पहले ही अनेक विकासशील देशों को ऋण के बोझ तले दबा चुका है। इसलिए कनेक्टिवी परियोजनाओं के स्तर पर भी, अमेरिका-नीत पश्चिम और चीन के बीच विश्व के उस हिस्से में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता पहले ही विकसित हो चुकी है।

अब इस प्रकार की नई उभरती शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता में, कुछ बड़े बदलाव देखने योग्य हैं। पूर्व और दक्षिणपूर्व एशिया में जापानोफोबिया जो द्वितीय- विश्व युद्ध के बाद दशकों तक कायम रहा, लगता है खत्म हो चुका है।

उस समय को याद करें जब कुछ दक्षिणपूर्व एशियाई देश कहा करते थे, हम "जापान का स्थायी समाधान" चाहते हैं। और आज, कम- से- कम 2010 के बाद से तो जरूर, एक नया बदलाव देख रहे हैं जिसमें जापान को राजनीतिक रूप से अधिक स्वीकृति मिल रही है और इसकी उभरती रक्षा स्थिति एवं क्षेत्रीय सुरक्षा पहल इस क्षेत्र के देशों के लिए कोई समस्या नहीं पैदा करती हैं। हालांकि जापान ने तथाकथित योशिदा सिद्धांत में आंशिक संशोधन किया है और निस्संदेह, नई सुरक्षा नीतियों को अपनाया है, लेकिन उसने अपने देश में असंख्य अमेरिकी सैन्य सुविधाएं और लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिकों को भी रखा है।

इसके साथ ही, जापानी नीति निर्माता व्यवस्थित रूप से रक्षा और सुरक्षा नीतियों को अपना रहे हैं जो राजनीतिक सुरक्षा मामलों और अंतरराष्ट्रीय मामलों में देश की भूमिका से संबंधित अन्य परंपरागत प्रतिबंधों को दरकिनार कर देते हैं। ऐसा लगता है कि चीन की आक्रामक मुद्रा और मुखर नीतियों एवं उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल जुझारूपन ने जापान को अपनी रक्षा एवं सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने को विवश कर दिया है। जापान की उभरती रक्षा एवं सुरक्षा स्थितियों के उदाहरणों में शामिल है- इसका बढ़ता रक्षा व्यय जो इसके सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक है; अंतरिक्ष में सैन्य उपग्रहों का भेजना; विदेशों में हिथायर बेचना, युद्ध में मित्र देशों की मदद करना, ताइवन की जल सीमा के करीब रक्षा घेरे को बढ़ाना और अपनी मिसाइल क्षमताओं को बेहतर बनाना। गौरतलब है कि जापान कथित तौर पर अगले पांच वर्षों में लगभग 56 अरब डॉलर खर्च करने जा रहा है, इसके साथ ही यह रक्षा खर्च के मामले में पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इसके अलावा, जापानी सरकार ने अब जवाबी हमला करने की क्षमता वाली मिसाइलें बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया है जो फिर से अतीत में अकल्पनीय था।

दुनिया के इस हिस्से की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है टोक्यो की बेहतर होती रक्षा स्थिति के बावजूद जापानोफोबिया का गायब हो जाना।

यह "चीन के शांतिपूर्ण उदय" की अवधारणा की अप्रासंगिकता और चीन की सैन्य शक्ति एवं "भेड़िया योद्धा" कूटनीति की लगातार वृद्धि के कारण तेजी से बढ़ते सिनोफोबिया के उलट हुआ है।

साल 2035 तक चीन के पास 1,500 परमाणु हथियार हो जाएंगे, जो संख्या में लगभग अमेरिका और रूस के बराबर होंगे, इस रिपोर्ट पर किसी का ध्यान नहीं गया। हालाँकि, सिनोफोबिया एक अंतर्निहित धारा है, क्योंकि चीन के छोटे- छोटे पड़ोसी देश प्रतिशोध के डर से चीन के रवैये के बारे में चुप्पी साधे रखते हैं। चीन का डर केवल कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और पूर्वोत्तर एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के समय ही देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन पर कुछ अमेरिकी लेखों और वाद-विवादों में भी चीन की आक्रामकता और मुकरता के बारे में आशंकाएं देखी जा सकती हैं। आश्चर्य की बात नहीं है गुप्त या मुखर सिनोफोबिया ने पूर्वोत्तर एशिया में मिसाइल स्पर्धा, सैन्य क्षमता निर्माण और विभिन्न रक्षा एवं सुरक्षा गठबंधन गठन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। बेशक, क्षेत्रीय आशंकाओं में उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण श्रृंखला और आक्रामक अपशब्द भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया द्वारा जारी किए गए इस बयान कि- अगर दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की 0.0001 मिलीमीटर सीमा का भी उल्लंघन किया तो प्योंगयांग धरती से दक्षिण कोरिया का नामोनिशां मिटा देगा, के साथ उत्तर कोरिया का मिसाइल विकास कार्यक्रम, समुद्र के भीतर परमाणु हथियार, और यहां तक कि उनके द्वारा पेंटागन एवं ह्वाइट हाउस की ली गई तस्वीरों ने वैश्विक मीडिया में सुर्खियां बटोरी थीं।

कोरियाई प्रायद्वीप में, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया वस्तुतः युद्ध की स्थिति में हैं। वर्ष 1953 में तीन साल के कोरियाई युद्ध के बाद उन्होंने कभी शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए, तकनीकी रूप से वे युद्ध की स्थिति में हैं। अब, उत्तर कोरिया ने कहा कि दक्षिण कोरिया उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा, प्योंगयांग ने उन सभी एजेंसियों को बंद कर दिया है जो कोरिया एकीकरण वार्ता से जुड़ी थीं।

दक्षिण कोरिया ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। उसने समुद्री सैनिकों को उत्तर कोरिया के उकसावे पर पहले गोली चलाने और फिर रिपोर्ट करने का आदेश जारी कर दिया।

इसका मतलब है कि कोरियाई प्रायद्वीप खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। अगर हम, भारत में कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति पर तीन साल पहले बात कर रहे होते, तो शायद हम यह कहते कि "ये सब बेकार की बातें हैं", और वास्तव में वहां कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच, हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप में एक- के- बाद- एक बयानबाज़ी कोरी धमकियां हैं और कोई युद्ध नहीं होगा। कोरियाई प्रायद्वीप में सशस्त्र संघर्ष हो या न हो लेकिन राजनीतिक तनाव और आदान- प्रदान ने तनाव के स्तर को बढ़ा दिया है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव डाला है।

उत्तर कोरिया के रणनीतिक समर्थक, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास पूर्वोत्तर एशिया में रणनीतिक परिस्थितियों के लिए अपनी जिम्मेदारी है। बीजिंग उत्तर कोरिया को संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्र में उसके सहयोगियों के मुकाबले एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में उपयोग कर रहा है। चीन का व्यवहार आंशिक रूप से उसके उस विश्वास का कारण है कि अमेरिकी उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन की घोषित नीति चीन को प्रतिस्पर्धा में शामिल करना और चीनी नेतृत्व के साथ मिल कर काम करना है ताकि प्रतिस्पर्धा का संघर्ष में न बदला जाना सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन वास्तविकता में, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच कोई साधारण प्रतिस्पर्धा नहीं है। महामारी के माध्यम से, सीमा- शुल्क विवाद के माध्यम से, अमेरिका- चीन व्यापार पैटर्न ने उनके बीच जटिल शीत युद्ध में योगदान दिया है। इतना जटिल शीत युद्ध अमेरिका और चीन के बीच गहरी आर्थिक परस्पर निर्भरता का परिणाम है और इसकी तुलना अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच चले शीत युद्ध से नहीं की जा सकती। अमेरिका- यूएसएसआर प्रकार का शीतयुद्ध स्वचालित रूप से एमएडी सिद्धांत या पारस्परिक सुनिश्चित विनाश को लागू करेगा और वाशिंगटन या बीजिंग दोनों ही ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन साथ ही, प्रतिस्पर्धा जटिल है। कई अमेरिकी आधिकारिक दस्तावेज़ों में इस बात पर ज़ोर देकर कहा गया है कि अमेरिका विश्व में किसी भी प्रतिद्वंद्वी शक्ति के उदय को बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

और चीन एक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाली अव्वल प्रतिद्वंद्वी शक्ति है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका

को विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के स्थान से हटाना चाहता है, विशेषरूप से हिंद- प्रशांत क्षेत्र में। इसलिए चीन- अमेरिका तनाव एवं विवाद स्पष्ट है।

अब, भविष्य में क्या हो सकता है? सभी की निगाहें अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा? ये एक सवाल है जो अमेरिकी सहयोगियों और अमेरिका के विरोधियों के बीच हर किसी को, हर जगह परेशान कर रहा है। अब, जब ट्रम्प कहते हैं कि वे रूस को नाटो के सहयोगी राष्ट्रों पर भी हमला करने की अनुमति दे सकते हैं, विशेषरूप से उन देशों पर जो नाटो के कोष में पर्याप्त योगदान नहीं कर रहे हैं, तो केवल भौंहें ही नहीं तन जाती हैं, बल्कि नाटो के भविष्य पर गंभीर पुनर्विचार भी शुरू हो जाता है।

तो, अगर अमेरिका में ट्रम्प 2.0 शासन आ गया तो हिंद- प्रशांत में क्या हो सकता है? देखिए, तथाकथित क्वाड 10 सालों से निष्क्रिय था। ट्रम्प ने इसे फिर से सक्रिय बनाया। और फिर बाइडेन ने इसे जारी रखा। इसकी पूरी संभावना है कि अगर वाशिंगटन डीसी में सत्ता बदल भी जाती है और ट्रम्प राष्ट्रपति बन जाते हैं, तब भी चतुर्भुज सुरक्षा पहल जारी रहेगी। पिछले दिन, अमेरिकी कांग्रेस ने क्वाड राष्ट्रों के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए क्वाड बिल पारित किया था, इसलिए यह काम करता रहेगा।

ऑकस (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंग्डम और अमेरिका- AUKUS), एक और व्यवस्था है जहां अमेरिकी वर्चस्व के लिए चीनी आकांक्षाओं को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव भले ही ट्रम्प जीतें लेकिन यह खत्म होने वाला नहीं है। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और जापान एवं दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के सहयोगी संबंधों का क्या होगा, यह गंभीर प्रश्न है। जब 2017 में ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने कहा था कि वे गठबंधन में विश्वास नहीं करते और अगर जापान चाहे तो परमाणु ऊर्जा संपन्न बन सकता है। क्या वे जापान के साथ दशकों से चले आ रहे गठबंधन संबंधों को जारी रखेंगे और विस्तारित परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। दक्षिण कोरियाई नेतृत्व ने हाल ही में कहा था कि यदि अमेरिका परमाणु सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा तो सियोल अपना परमाणु हथियार भी विकसित कर सकता है।

बाइडेन प्रशासन ने बहुत तत्परता के साथ राजनीतिक दबाव डाला और मामले को एजेंडे से हटा दिया गया है, क्या ट्रम्प दक्षिण कोरिया को परमाणु ऊर्जा संपन्न बनने की अनुमति देंगे या अप्रत्यक्ष रूप से उसे विवश करेंगे? अभी यह तय करना मुश्किल है। विश्व के इस हिस्से में और अधिक परमाणु हथियार संपन्न देशों के उभरने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है।

राजदूत स्कंद तयाल

धन्यवाद, प्रो. महापात्रा। तो एशिया में शायद और कई परमाणु संपन्न राष्ट्र होंगे। लेकिन जापानोफोबिया के कम होने बात बहुत मान्य है। नम्रता अब आपकी बारी।

डॉ. नम्रता हसीजा

धन्यवाद सर और मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आईसीडब्ल्यूए को धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे अपने प्रोफेसरों, जिन्होंने वास्तव में दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ाया था, के बाद बोलने का अवसर मिला है लेकिन अपने वरिष्ठों के साथ एक ही पैनल में होना शानदार है।

तो, चलिए मैं ताइवान के चुनाव के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं बहुत ही जानकार दर्शकों से बात कर रही हूं इसलिए मैं पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगी। आप जानते हैं कि डीपीपी क्या है, केएमटी क्या है। अब मैं वास्तव में को वेन- ज़ी से शुरूआत करना चाहती हूं। अब को वेन- ज़ी, मैं इनसे ही क्यों शुरूआत करना चाहती हूँ और मैं इनके बारे में क्यों बात करना चाहती हूँ क्योंकि ताइवान के चुनाव के बाद, इस बार यह बहुत करीबी मामला रहा और क्योंकि पिछले दो चुनाव, उनके लिए जिन्होंने चुनाव पर नज़र बनाई हुई थी, यह स्पष्ट था की जनाधार डीपीपी के साथ है। लेकिन इस चुनाव से पहले, आप जानते हैं, हममें से कुछ लोगों ने, जो मेरी ही तरह चुनाव पर नज़र बनाए हुए थे, हमने वास्तव में भविष्यवाणी की थी कि शायद राष्ट्रपति चुनावों में डीपीपी जीत जाएगी लेकिन विधायी युआन में डीपीपी बहुमत खोने जा रही है और वही हुआ। और बहुमत में मिली इस हार के कारण को वेन- ज़ी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अब को वेन- ज़ी ताइवाइन पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस पार्टी का गठन वास्तव में 2019 में हुआ था और यदि आप वोट शेयर पर नज़र डालें तो इन्हें कुल 26.46% वोट मिले थे। डीपीपी को 40 मिले जो 40.05% है, यदि आप पिछले दो बार से तुलना करें तो यह इसका सबसे कम वोट प्रतिशत है। क्योंकि राष्ट्रपति

साई इंग- वेन वास्तव में इससे भी बड़े जनादेश के साथ आईं। और फिर, निश्चित रूप से, केएमटी, जो ब्लू पार्टी है, जिसे 33.49% वोट शेयर मिला।

मेरे लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विधायी युआन में, अगर आप देखेंगे तो केएमटी की 52 सीटें हैं और डीपीपी की 51सीटें। और टीपीपी जो गेम चेंजर हो सकती है, उसके पास 8 सीटें हैं। शुरुआत में, चुनाव से पहले, केएमटी और टीपीपी, ने गठबंधन बनाने का प्रयास किया जो निश्चित रूप से बन नहीं पाया। और वास्तव में हम जैसों के लिए जो इन चुनावों पर नज़र बनाए हुए थे, बहुत सारा नाटक किया गया क्योंकि वे हयात होटल में मिले थे। और वे इस बात पर आपस में झगड़ रहे थे कि तुमने मुझे अच्छा कमरा नहीं दिया और ऐसी ही अन्य बेकार की बातों पर बहस कर रहे थे। एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया जैसा किसी भी लोकतंत्र में होती है। लेकिन बहुत दिलचस्प है कि डीपीपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। इसलिए, जब घरेलू नीतियों या विदेशी नीतियों की बात आती है तो उन्हें टीपीपी या कुछ हद तक स्वतंत्र लोगों के समर्थन की भी आवश्यकता होगी। इसलिए, यहां मैंने को वेन- ज़ी से शुरुआत की, क्योंकि वह गेम चेंजर हो सकते हैं।

अब, उनके पास डीपीपी के साथ भी काम करने का अनुभव है। लेकिन बाद में, बेशक, उनका डीपीपी से मतभेद हो गया और इसी वज़ह से, चुनाव से पहले, उन्होंने केएमटी के साथ साझेदारी करने की कोशिश की। अब, वो कुछ ऐसे हैं, मेरा मतलब है, इसे ह्वाइट पार्टी कहा जाता है। ताइवान में, जब हम वहाँ थे तो बहुत दिलचस्प बात हुई थी, हम हमेशा लोगों से पूछते थे कि वे लोग नीले के पक्ष में हैं या हरे के। लेकिन अब, एक तीसरी पार्टी है, ह्वाइट पार्टी और जिसने अपने वोट शेयर से कई लोगों को अचंभित कर दिया है। लेकिन ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या ये पार्टी महज़ एक बुलबुला है? क्योंकि बहुत सारे युवा नीतियों, विशेषरूप से घरेलू नीतियों में ठहराव के कारण डीपीपी को वोट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि उनको वेतन नहीं मिल रहा था, मेरा मतलब है कि, उनका वेतन कई सालों से नहीं बढ़ाया गया था। और अर्थव्यवस्था भी उन कारकों में से एक है जिसके लिए युवाओं ने वास्तव में इस टीपीपी पार्टी को वोट देना चुना।

तो, क्या वे इसे बरकरार रख सकते हैं या यह केवल इस चुनाव का बुलबुला है? क्योंकि बहुत से लोग को वेन- ज़ी पर विश्वास नहीं है क्योंकि वह कई बार पाला बदल चुके हैं। और साथ ही, एक समय ऐसा भी था जब लोग उनके बारे में यह बोलते थे कि ये ऐसा इंसान है जो पीआरसी से पैसे ले रहा है।

अब निश्चित रूप से डॉ. लाई हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और इसलिए डॉ. लाई उस गुट से हैं जिसे डीप ग्रीन कहा जाता है, जो स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। तो, आप जानते हैं कि, उन्हें ताइवान की स्वतंत्रता का गोल्डन ग्रैंडसन (स्वर्णपौत्र) भी कहा जाता है। इसलिए, जब ताइवाइन की स्वतंत्रता की बात आती है तो उनकी नीतियां शुरू में बहुत सख्त जान पड़ती हैं।
लेकिन समय के साथ उनकी नीतियों में बदलाव आया है और इस चुनाव से पहले, उन्होंने सच में अलग- अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने शिक्षाविदों, विशेषज्ञों के दलों, अर्थशास्त्रियों तक से मुलाकात की जो केएमटी के समर्थक भी रहे हैं। इसलिए, उन्होंने एक प्रकार से शामिल होने, सभी को शामिल करने और दूसरों के विचार जानने का प्रयास किया।

तो अब निश्चित रूप से, केएमटी उम्मीदवार श्री हो हैं। जैसे कि मैंने बताया, उन्हें भी 33% वोट मिले हैं। अब जब टीवी देख रही थी, हर कोई यही कह रहा था कि ताइवान ने चीनीयों को- चीन के हस्तक्षेपों को नकार दिया है और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए वोट डाला है। मुझे नहीं लगता कि ताइवान के लोगों ने वास्तव में इस कारण के साथ वोट डाला है।

और शायद, आप जानते हैं, मैं अब "क्यों" पर चर्चा करूँगी। क्योंकि मेरे लिए डॉ. लाई की नीतियां अब स्वतंत्रता पर वास्तव में कट्टर होने की तुलना में अधिक व्यावहारिक रही हैं।
उन्होंने वास्तव में राष्ट्रपति बनने से पहले भी साक्षात्कार दिया था और कहा था कि ताइवान औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करेगा और आप जानते हैं कि उन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है- डीपीपी को वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब हो, जो केएमटी के एक उम्मीदवार हैं, ने 1992 के मतैक्य को स्वीकार कर लिया है। अब 1992 का मतैक्य तब का है जब आरओसी और पीआरसी दोनों ने यह मान लिया था कि एक ही चीन है लेकिन दोनों की व्याख्याएं अलग- अलग हैं।
अब उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 1992 के मतैक्य को डीपीपी ने न तो कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया ना ही उसका सार्वजनिक खंडन।

अब वे निश्चित रूप से डीपीपी द्वारा 1992 के मतैक्य को अस्वीकार करने के बारे में बहुत मुखर रहे हैं और उन्होंने दबाव को कम करने के लिए चीनीयों के साथ मिल कर काम करने की बात भी की है क्योंकि जब मुझे केएमटी विधानमंडल के एक से अधिक सदस्यों का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला तो उन सब ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य तनाव, समुद्री- सीमा के पार वाले तनाव को कम करना है, क्योंकि हम नहीं चाहे की हमारी आने वाली पीढ़ी युद्ध में उलझ कर रह जाएं। इसलिए, चुनाव प्रचारों में भी वे यही बात कहते नज़र आए।

अब को वेन- ज़ी की स्थिति, जैसा कि मैंने कहा, वे न इधर के रहे ना उधर के। अब उन्होंने निश्चित रूप से इस बारे में बात की है कि वास्तव में उन्हें एक परिवार की तरह समुद्री- सीमा के दो पक्ष कैसे होने चाहिए और उन्होंने इस नीति में पांच संबंधों के बारे में बात की। लेकिन 1992 का मतैक्य पर, उन्होंने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं की क्योंकि वे पूरी तरह से खारिज़ नहीं किए गए थे लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार भी नहीं किया है। अलग- अलग समय पर अलग- अलग बयान दिए गए हैं।

अब ये महत्वपूर्ण क्यों हैं और हम वास्तव में 1992 की आम सहमति पर उनकी स्थिति के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर समुद्री- सीमा पार संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा।

अब चुनाव के ठीक बाद, पेलोसी के दौरे के बाद हमने जो देखा, वह चुनाव के बाद नहीं देखा। कोई बड़ा पीएलए अभ्यास नहीं हुआ है। वास्तव में, चुनाव के दिन ताइवन के आस पास कोई पीएलए विमान या ताइवान का एडीआईजेड नहीं था, हालांकि पीआरसी गुब्बारों के होने की रिपोर्ट की गई लेकिन पीएलए विमान नहीं ता। लेकिन राष्ट्रपति के रूप डीपीपी उम्मीदवार की जीत के दो दिनों के बाद, नाउरू ने ताइवान से अपना राजनयिक समर्थन वापस ले लिया और उन्होंने पीआरसी को मान्यता दे दी।

अब चीन ने भी 14 जनवरी के बाद से क्रॉस- स्ट्रेट लाइन (समुद्री जलसीमा) के साथ- साथ सैन्य उड़ानें आरंभ कर दीं। और हाँ, चीन, मेरा मतलब है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि, उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वे शायद उनके उद्घाटन भाषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि चीन निकट भविष्य में आर्थिक सैन्य दबाव बढ़ा सकता है। अब 17 और 18 जनवरी को, हमने देखा कि पीएलए के 24 विमान द्वीप पर मंडरा रहे थे, जबकि

कुछ ने दुर्लभ, रात के समय भी गश्त लगाई।

तो अब ताइवान में हुए चुनावों का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और यही मुख्य सवाल है। और क्रॉस- स्ट्रेट (समुद्री जलसीमा के परे) संबंध कैसे होंगे? अब किसी भी प्रमुख विदेश नीति निर्णय हेतु, जैसा कि मैंने कहा, डीपीपी के पास बहुमत नहीं है। इसलिए, इसे टीपीपी या कुछ सीमा तक, निर्दलीयों के समर्थन की और केएमटी से भी समर्थन की आवश्यकता होगी। और राष्ट्रपति लाई पहले ही कह चुके हैं कि वे राष्ट्रपति साई इंग- वेन की नीतियों का पालन करने वाले हैं। कोई प्रमुख बदलाव नहीं होगा।

और जैसा कि मतदान को मैं देख पा रही हूँ और मैं यह क्यों कह रही हूँ कि मेरे विचार उन ब्रेकिंग सुर्खियों से, कि, ताइवानियों ने वास्तव में चीनियों के खिलाफ मतदान किया है, क्यों अलग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ताइवान के लोगों ने, हाँ, संभवतः उन्होंने चीन समर्थक पार्टी को राष्ट्रपति पद के लिए अस्वीकृत कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत व्यावहारिक तरीके से मतदान किया है। उन्होंने दोनों घरेलू नीतियों में यह बात शामिल की है कि वे चाहते थे कि डीपीपी बदले और उन्होंने स्थिति को पूर्ववत रखने के लिए भी मतदान किया है। क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी जनमत सर्वेक्षण कराए गए थे जिसमें ताइवान की 80% जनता ने कहा था कि वे पहले जैसी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए, मैं कहना चाहूँगी कि इसे कुछ इस तरह बनाए रखने की बजाए, मुझे लगता है कि ताइवान की जनता ने यथास्थिति के लिए मतदान किया है और घरेलू नीतियों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।

और जब बात क्रॉस- स्ट्रेट संबंधों (समुद्री सीमा के परे संबंधों) की आती है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल, चीन की प्रतिक्रिया के जैसे ही, जब तक कि उनका भाषण, उद्घाटन भाषण, नहीं हो जाता, या तो वे उद्घाटन भाषण के दौरान, यदि वे कुछ कहते हैं या उसके बाद, कोई ऐसी नीति हो जिसमें डॉ. लाई सीमा रेखा का उल्लंघन करते हैं, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे ऐसा करेंगे। इसलिए, मैं सिर्फ परिस्थितियां बता रही हूँ, क्या हो सकता है, चीन द्वारा सैन्य बल के उपयोग की संभावना बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वे सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो अभी के लिए, चीन ऐसा नहीं करने जा रहा है। और ऐसा न करने के तीन कारण हैं।

पहला, यदि आप चीन के सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं, विशेष रूप से वीबो और दूसरे अकाउंट्स पर, तो उन पर ताइवान के चुनावों के बारे में चर्चा करने पर एक प्रकार का प्रतिबंध नज़र आता है, लेकिन वे हमेशा इस पर चर्चा करने के लिए गुप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। और साथ ही चीन की सरकारी मीडिया की ओर से जो कुछ भी कहा गया है, उसमें डॉ. लाई की जीत को नकारा गया है। उनका कहना है कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, बेशक, क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिला है। इसलिए ताइवान में सभी लोग, और विशेष रूप से वोटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, यदि आप केएमटी और टीपीपी दोनों को एक साथ जोड़ दें, दोनों ने वास्तव में बेहतर क्रॉस-स्ट्रेट संबंधों के बारे में बात की थी, तो उनके पास डॉ. लाई के मुकाबले अधिक वोट हैं।

जी हाँ, मैं बस अपनी बात समाप्त ही कर रही हूँ। दो और बातें। और फिर, निस्संदेह, हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि चीन की अपनी आर्थिक समस्याएं हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ तो पीएलए रॉकेट फोर्स में एक बड़ा फेरबदल या बड़ी बर्खास्तगी हुई है। इसलिए हमें इस पर भी विचार करना होगा। और मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यदि कुछ भी होता है, यदि सीमा रेखा का उल्लंघन किया जाता है, तो इनमें से कोई भी वास्तव में शी जिनपिंग को रोक सकेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होता, तो ये वो बातें हैं जिन पर वे विचार कर सकते हैं, कि संबंध अच्छे बने रहें और वर्तमान में कोई सैन्य संकट पैदा नहीं होगा।

और साथ ही, मेरे लिए मुख्य कारक, जो कि क्रॉस- स्ट्रेट संबंधों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, या जो क्रॉस- स्ट्रेट संबंधों को किसी भी दूसरे कारण की तुलना में अधिक प्रभावित करता है, वह है अमेरिका- चीन कारक। वर्तमान में, बैठक के बाद, विशेष रूप से नवंबर में हुई बैठक के बाद, कम- से- कम मुझे तो लगता है कि अमेरिका ने चीन की तरफ शांति के कदम बढ़ाए हैं। और वे अमेरिका- चीन संबंधों में स्थिरता भी लाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ तक चीन, मेरा मतलब है कि, अमेरिका- चीन संबंध की बात है, या तो स्थिर है या प्रगति के पथ पर है क्योंकि जब बात चीन द्वारा सैन्य बल के प्रयोग न करने की आती है तो अमेरिका सबसे बड़े प्रतिवारक की भूमिका में नज़र आता है क्योंकि यह ताइवान की सेना नहीं है, यह कुछ और नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि यह अमेरिका ही है जो प्रतिवारक बना हुआ है और मुझे लगता है कि यह प्रतिवारक बना रहेगा।

डॉ. स्तुति बनर्जी

राजदूत स्कंद तयाल डॉ. नम्रता हसीजा

राजदूत स्कंद तयाल

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। संभव है प्रश्नोत्तर सत्र में मैं कुछ और जानकारी आपसे साझा करूँ। धन्यवाद।

धन्यवाद नम्रता। जी हाँ, अमेरिका प्रतिवारक ही है। और कोई भी आपकी इस बात से सहमत होगा कि ताइवान को अच्छी तरह से बताया जाए कि वह किसी भी तरीके से स्थिति को बदलने का प्रयास न करें और अपनी स्थिति में खुश रहे।

चलिए, बहुत कम समय रह गया है, तो अब प्रश्नोत्तर का दौर शुरू करते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछें।

धन्यवाद। आपका बहुत, बहुत धन्यवाद। मैं डॉ. स्तुति बनर्जी हूँ। मैं परिषद में अध्येता (रिसर्च फेलो) हूँ। मेरा प्रश्न डॉ. नम्रता हसीजा से है। आपने अभी- अभी ताइवान के बारे में बात की। इस पैनल का कोई भी सदस्य अमेरिका- चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों के बारे में बात कर सकता है। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आप अमेरिका- चीन, रूस के संबंधों के बीच ताइवान को कैसे फिट करेंगी? और जैसा कि हम अमेरिका में नए चुनावों पर विचार कर रहे हैं, यदि नेतृत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो आप नेतृत्व में होने वाले इस परिवर्तन को विदेश नीति के दृष्टिकोण और अभी- अभी आपने जिस प्रतिवारक भूमिका के बारे में बात की, उसको किस प्रकार प्रभावित होता देखती हैं? धन्यवाद।

आप उत्तर दे सकती हैं।

ठीक है, निश्चित रूप से ताइवान पूरे अमेरिका- चीन परिदृश्य में फिट बैठता है, आप जानती हैं, हम जिस संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप देखे, विशेष रूप से बीते आठ, नौ वर्षों की घटनाओं पर नज़र डालें तो मैं कहूँगी कि खासतौर पर डीपीपी के आने और अमेरिका- चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू होने के बाद, मुझे लगता है कि ताइवान उन कारकों में से एक रहा है जिसके बारे में यदि आप चीन की आधिकारिक मीडिया और चीनी भाषा की मीडिया को पढ़े तो, मेरा मतलब है कि वे अमेरिका- चीन के संबंधों की बात करते समय ताइवान की बात सबसे अधिक करते हैं। और वे यह भी कहते हैं कि अमेरिका की बात आती है तो ताइवान सीमा रेखा है। अगर आप शी जिनपिंग और बाइडेन की बीच हुई हालिया बैठक की बात भी करें तो इस संदर्भ में ताइवान का जिक्र किया गया था। और हम कह सकते हैं कि ताइवान सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक है क्योंकि अभी लहर का प्रभाव सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला करता है और बस, हम इससे बाहर हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पूरे हिंद- प्रशांत क्षेत्र पर पड़ेगा और हर कोई इसे महसूस करेगा।

डॉ. संदीप मिश्रा

दूसरा है ताइवान पर अमेरिका की नीति, मैं यह नहीं कहूँगी कि, यदि आप फिर से देखें, तो हाँ, आपने नेतृत्व में बदलाव की बात की है। लेकिन मेरे लिए, अमेरिका की नीति और हथियारों की बिक्री रिपब्लिकन सरकार के समय भी थी और अब भी है। इसलिए वह समर्थन जारी रहेगा।

यदि अमेरिकी सरकार में परिवर्तन होता है, तब भी ताइवान को समर्थन जारी रहेगा क्योंकि ताइवान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। यह अमेरिका के लिए पहला द्वीप श्रृंखला है और साथ ही वहां की सेमीकंडक्टर उद्योग के कारण भी। हमें सेमीकंडक्टर उद्योग को ध्यान में रखना होगा।

इसलिए, मुझे लगता है कि अमेरिका का समर्थन जारी रहेगा, चाहे अमेरिका में किसी की भी सरकार बने।

डॉ. श्रीपति नारायण

अगर अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं दो प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला, उत्तर कोरिया का जो रवैया है, क्या दुनिया में ऐसा कुछ है जिसे उत्तर कोरिया को दिया जा सकता है या कोई समझौता किया जा सकता है जिससे वह अपने पड़ोसी देशों के साथ

अधिक शांतिपूर्ण तरीके से रह सके? और कुछ प्रकार के हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण के संदर्भ में नहीं, बल्कि मिसाइलों के परीक्षण और फायरिंग पर रोक लगाई जा सकती है।

दूसरा प्रश्न यह है कि, अध्यक्ष महोदय ने आरंभिक टिप्पणी में दो अर्ध-सहयोगी राष्ट्रों का उल्लेख किया था, जो पश्चिम में ईरान और पूर्व में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक है। इस नाज़ुक परिस्थिति में भारत का स्थान क्या है? या क्या भारत अपने लिए जगह तलाश पाया है?

मैं कहूँगा कि अगर हम उत्तर कोरियाई शासन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि उनके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम सुरक्षा के साथ- साथ घरेलू वैधता के लिए भी हैं। इसलिए, यदि हम किसी तरह से उत्तर कोरिया को किसी प्रकार की सामूहिक सुरक्षा गारंटी प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि पांच देशों (रूस, अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया) द्वारा यह आश्वासन कि वे सामूहिक रूप से या द्विपक्षीय रूप से उत्तर कोरिया पर हमला नहीं करेंगे या उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे,

म कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा, उत्तर कोरिया अधिकांश विकासात्मक मापदंडों पर खराब प्रदर्शन कर रहा है और इसका खामियाज़ा उत्तर कोरिया की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम एक प्रतीक प्रदान करता है जिस पर उत्तर कोरिया के लोग गर्व करते हैं और इस प्रकार उत्तर कोरियाई शासन को घरेलू वैधता प्रदान करते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यदि शासन को आर्थिक वृद्धि और विकास जैसे कुछ अन्य स्रोतों से अपनी वैधता मिल सकती है तो शायद उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने के बारे में विचार कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ दो असंभव प्रतीत होने वाले प्रस्ताव हैं और इन्हें साकार करना आसान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि राजदूत तयाल ने जो कहा, उत्तर कोरिया का अपना परमाणु मिसाइल कार्यक्रम बंद कर असंभव है, वह बहुत यथार्थवादी आकलन है। इसलिए, हम उत्तर कोरिया द्वारा अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बजाए उसके निवारण पर विचार कर सकते हैं। किसी भी अन्य बातों से अधिक, हमें उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। भले ही उत्तर कोरिया का व्यवहार भड़काने वाला हो या स्वीकार्य न हो, फिर भी उसके साथ बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए।

तो, बातचीत का विषय परमाणु निरस्त्रीकरण से बदलकर हथियार

राजदूत स्कंद तयाल
प्रो. चिंतामणि महापात्रा

तो उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्र

नियंत्रण करना होगा। आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। कृपया दूसरा प्रश्न का उत्तर दें।

पहले प्रश्न के उत्तर में भी, हथियारों पर किस प्रकार का नियंत्रण? यह एकतरफा नहीं हो सकता। उत्तर कोरिया कृपया आप अपने हथियारों या मिसाइल परीक्षणों को कम कर दें। ऐसा नहीं होने जा रहा है। उत्तर कोरिया की संसद पहले ही एक कानून पारित कर चुकी है जिसके अनुसार परमाणु निरस्त्रीकरण पर कोई चर्चा नहीं की जाएगा। इसलिए, उत्तर कोरिया वास्तव में एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है और दूसरे देश इस बात को स्वीकार कर भी सकते हैं और स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं लेकिन वास्तविकता यही है। इसलिए, इसके बारे में भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।

यदि आप उत्तर कोरिया की नज़र से देखें तो उन्हें परमाणु परीक्षण करने का अधिकार है और क्यों न हो? एक समय वे एनपीटी का हिस्सा थे, वे उचित तरीके से एनपीटी से बाहर निकले और एनपीटी के किसी भी नियम का अब तक उल्लंघन नहीं किया। वे अपनी सैन्य और सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। वे बेहद उत्तेजक अमेरिकी, कोरियाई, जापानी सैन्य अभ्यासों के कारण खतरा महसूस करते हैं। इसलिए, यदि आप उनके नज़रिए से देखेंगे तो पाएंगे कि यह केवल देश की सुरक्षा के लिए है और कौन है जो उन्हें बता सकता है कि नहीं, नहीं, आप तो बहुत सुरक्षित है, कृपया इस प्रकार के

प रीक्षण न करें।

ऐसा करने से कुछ नहीं होगा।

आप खुद ही देखें और आप जानते हैं कि अब इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के लोग भी पूर्वोत्तर एशिया समेत हिंद-प्रशांत में हो रही घटनाओं पर गहरी दिलचस्पी रखने लगे हैं। इटली बीआरआई से बाहर निकल चुका है। उसने जापान के साथ समझौता किया है। जर्मनी भी बाहर निकल गया है। सैन्य समझौते। जापान ने इन सभी देशों के साथ सैन्य रसद विनिमय अनुबंध किए हैं। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर कोरिया स्थिति में किसी तरह का बदलाव करने जा रहा है और भारत निश्चित रूप से संवाद और कूटनीति के स्तर पर भूमिका निभाएगा। वहाँ कोई भी युद्ध नहीं चाहता। युद्ध होने भी नहीं जा रहा है लेकिन जो हो रहा है वह है तनाव का बहुत अधिक बढ़ जाना और यह तनाव अभी जारी रहेगा।

ताइवान पर, महोदय, सिर्फ एक पंक्ति। ताइवान के लिए स्वतंत्रता की घोषणा उसके हित में नहीं है। यहां तक की डीपीपी भी इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा बहुत बड़े स्तर पर समर्थन के बगैर, वे ऐसा नहीं कर सकते।

चीन की कूटनीति के कारण उन्हें मान्यता देने वाले देशों की संख्या दिन- प्रतिदिन कम होती जा रही है। अमेरिका कभी भी ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करना नहीं चाहेगा। इन

राजदूत स्कंद तयाल

डॉ. मनोज पाणिग्रही

सारी बातों का सार है - यथास्थिति बनी रहे।

यथास्थिति बनी रहने से सभी को लाभ होगा, चीन को भी। इसलिए, असली समस्या चीन है। चीन के कायाकल्प के लिए, वे, सेना की मदद से संभव हो सके तो 2027 तक ताइवान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके बाद चीन द्वारा अपनाए जाने वाले रुख के संदर्भ में भारत समेत सभी के लिए समस्या पैदा हो जाएगी।

एक आखिरी सवाल।

मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए अध्यक्ष महोदय और आईसीडब्ल्यूए का धन्यवाद। मेरा सवाल प्रोफेसर मिश्रा से है। महोदय, आपने अलग-अलग गठबंधनों की बात की ।

तो, क्या मेरा ये कहना सही है कि हम इस क्षेत्र में द्विपक्षीय या बड़े हिंद- प्रशांत समूह की बजाय लघु- पक्षीय समूह को कार्यान्वित होते देख रहे हैं? क्या यह कहना उचित है कि बहुपक्षीय पूर्वोत्तर एशिया, पूर्वी एशियाई क्षेत्रों तक पहुँचने का नया रास्ता है? इसमें अमेरिका, जापान और कोरिया की त्रिपक्षीय बैठकें या चीन, जापान, कोरिया दोनों शामिल हैं?

और दूसरा सवाल होगा: हम सभी जानते हैं कि ताइवान ने बहुत सारे राजनयिक सहयोगियों को खो दिया है, और अब उनके पास केवल 12 सहयोगी बचे हैं। इसलिए, यदि ताइवान अपने सभी राजनयिक सहयोगियों को खो देता है तो क्या ताइवान के लिए दुनिया में अपनी आवाज़ उठा पाना संभव होगा? मेरा सवाल यही है।

मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के जटिल समीकरणों को देखते हुए बहुपक्षीय होना निश्चित रूप से अधिक प्रभावी रहेगा। लेकिन वर्तमान बहुपक्षीय पक्षों के अलावा, मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में अधिक अतिव्यापी लघुपक्षीय पक्षों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के वार्षिक बैठक बारे में बताया, इसे नियमित किया जा सकता है। बहुपक्षीय के माध्यम से काम करने के अलावा बहुस्तरीय

डॉ. नम्रता हसीजा

डॉ. संदीप मिश्रा

राजदूत स्कंद तयाल

अंतर्संबंधों का उपयोग लघुपक्षीय माध्यम से भी प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए

।

प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं। पहला, निश्चित रूप से, वो बहस जो चल रही है, ताइवान में भी, कि किस कीमत पर हम इन सहयोगियों को अपने साथ जोड़े हुए हैं? क्योंकि उनमें से ज्यादातर मिलने वाली भारी सहायता के कारण ताइवान के साथ है।

अब, दूसरा, बेशक, चीन किस तरह से ताइवान के लोगों को दबा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि वे ऐसा हर एक मोर्चे पर करना चाहते हैं और यह एक महत्वपूर्ण मोर्चा है। अब उनके पास केवल 12 सहयोगी बचे हैं और जब उनके पास एक भी सहयोगी नहीं रह जाएगा, तब एक भी देश नहीं बचेगा जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वास्तव में ताइवान के लिए आवाज़ बुलंद कर सकेगा। इसलिए, चीनियों की यह योजना हो सकती है कि यदि आप ताइवान से संबंध रखना चाहते हैं तो आप हमसे बात करें। यह भी एक तरीका है जिससे चीन ताइवान पर दबाव बना सकता है।

अच्छा, अब अंतिम प्रश्न, संक्षेप में।

प्रो. चिंतामणि महापात्रा

मैं माफी चाहती हूँ। नमस्कार। मुझे थोडी देर हो गई। और मैं प्रश्न पूछने वाली आखिरी शख्स हूँ। मेरा नाम अर्शी भारद्वाज है और मैं स्ट्रैटफोर न्यूज़ की शोध सहयोगी हूँ। मैं जानती हूँ कि हम सभी ने सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र के बारे में बात की है। मैं जनसांख्यिकी के बारे में एक बात आप सबके सामने रखना चाहूँगी, जनसांख्यिकी का मुद्दा जिसका सामना चीन और ताइवान दोनों कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे चीन सांस्कृतिक रूप से पूर्वोत्तर एशिया के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करते हुए उस मुद्दे को कैसे सुलझाएगा। और इससे आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या चीन, पूर्वोत्तर एशियाई देशों के साथ अपनी सांस्कृतिक समानता का उपयोग कर अपने संबंधों को सामान्य बनाने एवं बड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए युवाओं का सहयोग लेने का प्रयास कर सकता है।

मुझे इस पर कुछ बातें कहने दें। पहली, चीन की बूढ़ी हो रही आबादी एक मुद्दा है लेकिन चीन को उस प्रकार की आप्रवासन नीति की आवश्यकता नहीं है या वह ऐसी कोई नीति नहीं चाहेगा जिसके बारे में जापान ने विचार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जापान में भी बुजुर्गों की आबादी बहुत अधिक है, इसलिए जापान की सेना को लोगों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है?

दक्षिण कोरिया की भी यही स्थिति है। लोगों तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या दिन- प्रतिदिन बढ़ रही है।

इ
स
लि
ए
,
के
व
ल
ची
न
ही
न
हीं
ले
कि
न
इ
स
क्षे
त्र
के
क
ई
दे
शों
में

बूढ़ी होती आबादी एक समस्या है। इसका अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि श्रम बल के बिना, देश में युवा गतिशील लोगों के बिना आपकी आर्थिक विकास की दर का धीमा होना तय है।

तो, इससे किस तरह का प्रभाव होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

महोदय, बीस सेकेंड, इस लघु-पार्श्व मुद्दे पर। आपके पास अब चार देशों का समूह है। आपके पास कैंप डेविड, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। आपके पास जेआईए, जापान, भारत और अमेरिका है। आपके पास जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। आपके पास फ्रांस, जापान और भारत है। इसलिए यहां एक से अधिक त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय और लघु-पक्षीय समूह काम कर रहे हैं। यही समाधान है।

चीन किसी भी प्रकार के बहुपक्षीय संगठन को लेकर चिंतित है। वो क्वाड को एशिया का नाटो बताता है। इसलिए, इस तरह की कोई बात नहीं होने जा रही है। लेकिन लघु-पक्षीय एक बात है जिसके माध्यम से मुद्दे का समाधान किया जा सकता है।

डॉ. संदीप मिश्रा

एक छोटा सा स्पष्टीकरण मैं देना चाहूँगा। चीन वर्तमान में बुजुर्ग होता समाज नहीं बना है क्योंकि *एक चीन नीति* के प्रभाव के कारण ऐसा भविष्य में हो सकता है लेकिन फिलहाल यहाँ के लोगों की औसत आयु लगभग 39 वर्ष है। दक्षिण कोरिया और जापान निश्चित रूप से बुजुर्ग होता समाज है और जैसा कि राजदूत तयाल ने अपनी टिप्पणी में बताया बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। जनसांख्यिकी के अलावा मैं इस क्षेत्र के देशों जैसे चीन, जापान, कोरिया और ताइवान के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर बात करना चाहूंगा। तो, मुझे लगता है कि अगर उन्हें ऐसा करने की अनुमति मिलि तो यह सांस्कृतिक संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन देशों के बीच विवादास्पद जटिल मुद्दों के कारण ज्यादातर समय कोरियाई हल्लीयू या जापानी जे-पॉप एवं चीन की फिल्मों के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध वांछित सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे हैं। दरअसर, इन

राजदूत स्कंद तयाल

दे
शों
के
सां
स्कृ
ति
क
का
र्य
क्र
म
पू
रे
क्षे
त्र
में
ब
हु
त
लो
क
प्रि
य
है
,
ले
कि
न
इ
न्हें
इ
न
दे

शों की विदेश नीति निर्माण में कोई निर्णायक भूमिका निभाने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा होता है, तो यह बहुत अच्छा होगा और ऐसा होने की संभावना है।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद, विश्व व्यवस्था जो भी थी, वह सुलझ रही है और जैसा कि हेनरी किसिंजर ने भी लिखा है- एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान कम हो रहा है।

अमेरिका ने हमेशा से किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया है। तब चीन चुप बैठा रहा लेकिन चीन आक्रामक रूप से दक्षिण चीन सागर, हमारे गलवान आदि क्षेत्रों में बढ़ रहा है। फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब ईरान ने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला किया। इसलिए, ये सभी इस बात का संकेत हैं कि किस तरह क्षेत्रीय अखंडता की शुचिता के लिए जो सम्मान था, वह कम हो रहा है।

डॉ. तुनचिनमंग लंगेल

अब प्रशांत क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सब कुछ अभी अस्पष्ट है। आप अपना राष्ट्रीय हित देखते हैं और कोई नियम नहीं है। तो, देखते हैं यह कैसे होता है लेकिन स्थिति बहुत अनिश्चित है, चीजें लगातार बदल रही हैं।

राजदूत महोदय धन्यवाद। इस पैनल चर्चा की अध्यक्षता करने के लिए अपनी विनम्र सहमती देने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। आईसीडब्ल्यीए की ओर से, मैं सम्मानित पैनलिस्टों को अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा करने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस सार्थक सहभागिता में हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रतिष्ठित दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ।

पूर्वोत्तर एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों को समझना: क्षेत्रीय स्थिरता की खोज: आईसीडब्ल्यूए संवाद 40

कार्यक्रम

भारतीय वैश्विक
परिषद

आईसीडब्ल्यूए पैनल चर्चा

विषय

पूर्वोत्तर एशिया के जटिल और विकसित हो रही परिस्थितियों को समझना

क्षेत्रीय स्थिरता की खोज: आईसीडब्ल्यूए संवाद

16 फरवरी 2024 | 1100 - 1215 बजे

सम्मेलन कक्ष, सप्रू हाउस

कार्यक्रम*

1100-1110 बजे	**अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन भाषण** *राजदूत स्कंद आर. तयाल* *कोरिया गणराज्य और उज़्बेकिस्तान में भारत के भूतपूर्व राजदूत*
1110-1120 बजे	**डॉ. संदीप कुमार मिश्रा** *एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़,* *जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू), नई दिल्ली।*
1120-1130 बजे	**प्रो. चिंतामणि महापात्रा** *कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो- पेसेफिक स्टडीज़ के संस्थापक और मानद अध्यक्ष।* *पूर्व प्रो-वाइस चांसलर और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, जेएनयू, नई दिल्ली के प्रोफेसर*
1130-1140 बजे	**डॉ. नम्रता हसीजा** *अध्येता, सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी (सीसीएएस), नई दिल्ली*
1140-1210 बजे	अध्यक्ष द्वारा प्रश्नोत्तरी सत्र का संचालन
1210hrs IST	जलपान

** पैनल चर्चा का समन्वय आईसीडब्ल्यूए के अध्येता डॉ. तुनचिनमांग लांगेल द्वारा किया गया।*

बायो- प्रोफाइल्स

राजदूत स्कंद रंजन तयाल

राजदूत (सेवानिवृत्त) स्कंद रंजन तयाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है।

भारतीय विदेश सेवा (1976) में शामिल होने के बाद, राजदूत (सेवानिवृत्त) तयाल ने सोफिया, वारसॉ, जिनेवा और मॉस्को में भारतीय मिशन में अपनी सेवाएं दी हैं। वे जोहान्सबर्ग (1996-98) और ह्यूस्टन (2002-05) में भारत के महावाणिज्य दूत और उज़्बेकिस्तान में भारत के राजदूत (2005-08) थे। वर्ष 2008 से, वे कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत थे।

राजदूत (सेवानिवृत्त) तयाल 1991-95 के दौरान यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिव थे और उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में आईआईटी के प्रभारी निदेशक के रूप में भी कुछ समय के लिए काम किया है। वर्ष 1999-2002 के दौरान वे भारत के संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी रहे।

राजदूत (सेवानिवृत्त) तयाल को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति दोनों ही क्षेत्र का व्यापक अनुभव है और वे समसामयिक मामलों पर नियमित रूप से व्याख्यान देते रहे हैं।

जुलाई 2013 में राजदूत तयाल को नई दिल्ली के प्रसिद्ध दयाल सिंह कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। वे, 2012-15 में, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम और मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, नई

दिल्ली के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रहे।

राजदूत तयाल 2012 से 2016 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग में अतिथि प्राध्यापक थे।

राजदूत तयाल इंडिया- रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्रेंडशिप सोसायटी, नई दिल्ली के अध्यक्ष, सोसाइटी फॉर कॉम्प्लिमेंटरी थेरेपीज़, दिल्ली के सचिव और मिलेनियल इंडिया इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, दिल्ली के सलाहकार हैं।

डॉ. संदीप कुमार मिश्रा

डॉ. संदीप कुमार मिश्रा सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ (सीईएएस), स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ (आईसीएस), दिल्ली के मानद फेलो और इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फिल्क्ट स्टडीज़ (आईपीसीएस), नई दिल्ली के प्रतिष्ठित फेलो भी हैं। उन्होंने कोरियाई अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है। इन्होंने योनसेई यूनिवर्सिटी और सोगैंग यूनिवर्सिटी से कोरियाई भाषा का अध्ययन किया है। ये कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नॉर्थईस्ट एशिया हिस्ट्री फाउंडेशन, किम डे-जंग प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम, इंस्टीट्यूच फॉर फार ईस्ट स्टडीज़, क्यूंगनाम यूनिवर्सिटी, सेजोंग इंस्टीट्यूट और कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में विज़िटिंग फेलो और विज़िटिंग स्कॉलर रहे हैं।

इन्होंने किताबों में पाठों के साथ- साथ भारतीय और पूर्व एशिया के अकादमिक पत्रिकाओं में कई लेख लिखे हैं और कोरिया टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशल एक्सप्रेस, पायोनियर, ट्रिब्यून और स्टेट्समैन जैसे समाचारपत्रों में विचारपूर्ण लेख भी लिखे हैं।

इनके दिलचस्पी वाले क्षेत्रों में शामिल हैं- उत्तर कोरिया का परमाणु मुद्दा, पूर्वी एशिया के

अं त र	राष्ट्रीय संबंध, पूर्वी एशियाई सुरक्षा, एशिया- प्रशांत सुरक्षा आदि।

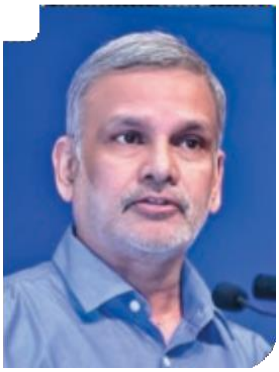

प्रो. चिंतामणि महापात्रा

प्रो. चिंतामणि महापात्रा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो- पेसेफिक स्टडीज़ के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं। ये जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर थे। इन्होंने 2016 से फरवरी 2022 की शुरूआत तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रेक्टर (प्रो- वाइस चांसलर) के रूप में काम किया है। ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स द्वारा प्रकाशित इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल के संपादक थे।

प्रो. महापात्रा ने आठ (8) किताबों का लेखन/ संपादन किया है और 30 से भी अधिक संपादित किताबों में अध्याय लिख कर योगदान दिया है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनके 70 से अधिक शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने पीएचडी के 26 और एम. फिल के 51 छात्रों का मार्गदर्शन किया है। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता की है और शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं।

इन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में शोध करने हेतु फुलब्राइट फेलोशिप, कॉमनवेल्थ फेलोशिप और विज़िटिंग फेलोशिप जैसी कई अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये

यू
जी
सी
द्वा
रा
सं
चा

लित अनेक अकादमिक स्टाफ
वाले कॉलेजों, विदेश मंत्रालय के
विदेश सेवा संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा
महाविद्यालय, आर्मी वार कॉलेज,
नेवल वार कॉलेज, और कॉलेज
ऑफ एयर वारफेयर में विज़िटिंग
प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी हैं।

डॉ. नम्रता हसीजा

नम्रता हसीजा सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी, नई दिल्ली में अध्येता हैं और उनकी प्राथमिक दिलचस्पी चीन की विदेश नीति और भारत-ताइवान संबंध है। इन्हें विदेश मंत्रालय से ताइवान फेलोशिप (2019-20) और शिक्षा मंत्रालय, ताइवान से हुआयू इनरिचमेंच स्कॉलरशिप (2014-15) मिल चुकी है।

सीसीएएस में शामिल होने से पहले वे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फिल्क्ट स्टडीज में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी थीं एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल चेंगछी यूनिवर्सिटी, ताईपे और नेशनल सिंग हुआ यूनिवर्सिटी, सिंगचू में अतिथि शोधकर्ता थीं। इन्होंने नेशनल चेंगछी यूनिवर्सिटी, ताईपे से एक वर्ष का गहन स्तर का मंदारिन भाषा सीखा है।

आईसीडब्ल्यूए के बारे में

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच. एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के समूह द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेस नीति के मुद्दों पर ज्ञान एवं विचार भंडार के रूप में काम करना था। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ- साथ अतिथि विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान के कार्य करती है। यह नियमित रूप से बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन करता है जिसमें सम्मेलन, सेमिनार, गोलमेज सम्मेलन, व्याख्यान भी शामिल होते हैं। परिषद प्रकाशन कार्य भी करता है। इसके पास समृद्ध पुस्तकालय है, इसकी वेबसाइट सक्रिए रूप से काम करती है और यह इंडिया नाम की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों में विकास करने हेतु आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ- समूहों और शोध संस्थानों के साथ 50 से अधिक अनुबंध किए हैं।

परिषद की साझेदारी भारत के अग्रणी शोध संस्थानों, विशेषज्ञ समूहों और विश्वविद्यालयों के साथ भी है।

भारतीय वैश्विक
परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली